(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नीलाम किये गये रेत और कचरे में पीतल, तांबा, शीशा और अन्य चीजों के टुकड़े रहते हैं; जिसके परिणाम-स्वरूप ठेकेदार भारी लाभ कमा रहे हैं;

(ग) क्या पीतल, तांबे और शीशे के छोटे-छोटे टुकड़ों को भी कचरे के रूप में नीलाम किया जाता है जिसके परिणाम-स्वरूप रेलवे को भारी हानि हो रही है; और

(घ) क्या सरकार का विचार रेलवे में व्याप्त ठेका प्रणाली को समाप्त कर रेलवे को होने वाली हानि से बचाने का है

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जो रेत, रद्दी लोहा और अन्य माल रेलवे के उपयोग के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है उसे जमालपुर स्थित भंडार डिपो द्वारा निविदा अथवा सार्वजनिक नीलामी के जरिए प्राप्त उच्चतम दरों पर बेच दिया जाता है। 1976–77 के दौरान लगभग 75 लाख रुपये की रद्दी लोहा बेचा गया। निविदाओं/सार्वजनिक नीलाम का प्रबन्ध रद्दी लोहे के पहिचाने जाने योग्य कोठियों में छंटाई करने के पश्चात् बेहतर मूल्य की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए तथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित कार्यविधि के अनुसार किया जाता है। इस प्रकार के निपटान से पहले तमाम रद्दी लोहे की अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की जाती है और केवल वही रद्दी लोहा बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसकी रेलवे को आवश्यकता नहीं होती।

(ङ) से (घ). उपर्युक्त (क). को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Exploration for Oil and Natural Gas in Rajasthan Desert

3272. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether oil or natural gas was discovered in the explorations done by Oil & Natural Gas Commission in the Rajasthan desert if so, where and at what depth the experimental drilling yielded success;

(b) whether Government propose to continue further drilling for finding oil or natural gas in this region;

(c) whether Government are aware of any misuse of funds and other misappropriations committed by ONGC officials in this project; and

(d) how much staff was posted for these tasks and what expenditure was incurred on these campaigns since the start of explorations?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) Except for a small gas find at Manhera Tibba at intervals between 287.5 to 464 metres, which was not of commercial significance, no hydrocarbons have so far been found in Rajasthan.

(b) Drilling in Rajasthan is being temporarily suspended for re-interpretation of the available data, on which would depend the future course of exploratory drilling there.

(c) A case of alleged temporary misuse of Commission's funds was looked into by the C.B.I. who referred the same to the O.N.G. Commission. The matter is under consideration of the Commission.

(d) The total strength of staff at the end of June, 1977 was 339 persons for the project and 51 persons

for seismic exploration work. The total expenditure incurred upto 31-3-1977 has been Rs. 12.42 crores approximately.

Appointment of High Court Judges

3273. SHRI OM PRAKASH TYAGI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state whether Government are considering a proposal for appointing High Court Judges from amongst the Advocates practising outside the States where they are appointed?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): Appointments of High Court Judges are made through procedures drawn up in accordance with article 217 of the Constitution, which does not stand in the way of appointment from amongst Advocates practising outside the States where they are appointed.

Wharfage Charges raised against Private Parties on Allahabad Division

3274. SHRI BATESHWAR HEMRAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the amount of wharfage charges raised against private parties on Allahabad Division for using railway godowns for the purposes of storing goods during the last 3 years, yearwise;

(b) the amount of wharfage charges foregone and finally recovered during the above-mentioned period;

(c) whether specific reasons were recorded by Commercial Officers while considering the request of parties for waiving of wharfage charges;

(d) whether Government are aware that some Commercial Officers in collusion with parties and brokers waived wharfage charges indiscriminately resulting into loss of railway revenue; and

(e) if so, what steps are proposed to be initiated to stop such malpractice?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रेलवे बोर्ड में तदर्थ आधार पर नियुक्ति

3275. श्री रामानन्द तिवारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड में बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव के विशेष सहायकों के पदों जैसे कुछ नाजुक पद वर्षों तक तदर्थ आधार पर प्रवर अधिकारियों को नजरअन्दाज करके भरे गये और सतर्कता विभाग ने भी इसका विरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है और गत दस वर्षों में उनके वेतनमान क्या थे और उन्हें कितना वेतन दिया गया ;

(ग) क्या उनको इस प्रकार की तदर्थ नियुक्तियों तथा रेलवे में राजपत्रित संवर्ग के बारे में कुव्यवस्था का पता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) उक्त दोनों पद केवल सीमित अवधियों के लिए तदर्थ आधार पर भरे गये थे, जैसा कि नीचे बताया गया है :—

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के विशेष सहायक—23-1-1974 से 5-2-1975 तक और 5-5-1977 से आगे

सचिव, रेलवे बोर्ड के विशेष सहायक 31-3-1973 से 22-1-1974 तक (श्रेणी II में) और 23-1-1974 से 23-3-1977 तक (श्रेणी I में)-